वाई. साराबा रेड्डी

बनाम

पुथुर रामी रेड्डी और अन्य

7 मई, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. के. बालासुब्रमण्यन और डी. के. जैन, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस.319-का दायरा और विशेष जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के बाद अभियुक्तों की श्रेणी में से किसी व्यक्ति का नाम हटाने की सीमा- प्राथमिकी और गवाहों के कथनों में पाए गए उनके नाम---धारा 319 के अधीन आवेदन-विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकृति-विलंब के आधार पर और अपील में शिकायतकर्ता के साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि--आयोजितः धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग स्वतः या आवेदन पर किया जा सकता है-हालाँकि, यह असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिए-विचारण न्यायालय के पास किसी व्यक्ति को अभियुक्तों की श्रेणी में जोड़ने और मुकदमे का चलाने का क्षेत्राधिकार है।-इस तरह का संयोजन केवल इसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है, मात्र आरोप पत्र या केस डायरी में सामग्री के आधार पर नहीं, क्योंकि ये साक्ष्य का गठन नहीं करता है- शिकायतकर्ता के बयान की विश्वसनीयता तय करने के लिए जांच अधिकारी से अभिलेख मंगवाना

एक असामान्य प्रक्रिया है-इसलिए निचली अदालत को धारा 319 के तहत कार्यवाही के लिए कदम उठाने का निर्देश।

पीडब्लू-1 (शिकायतकर्ता) द्वारा प्रतिवादी अभियुक्त के खिलाफ मृतक की मृत्यु के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। जांच पड़ताल की गई। अभियुक्त द्वारा किए गए एक आवेदन पर, पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मामले की जांच की गई और इसकी रिपोर्ट के आधार पर, अभियुक्तों की श्रेणी से उनके नाम हटा दिए गए। उन्हें आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता (पीडब्लू1) से पूछताछ के बाद, उसने प्रतिवादियों को आरोपी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए धारा 319 Cr.P.C के तहत एक याचिका दायर की। ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि उनके नामों को हटाने का निर्देश पुलिस अधीक्षक की संतुष्टि पर दिया गया था। राज्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता ने भी पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट होंने के लिए कि पीडब्लू-1 का संस्करण विश्वसनीय था या नहीं ने जाँच अधिकारी से रिकॉर्ड माँगा। फिर इसने निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की और यह भी माना कि प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी हुई थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 . धारा 319 Cr.P.C को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर और अदालतों द्वारा निर्धारित कानून से यह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट के पास

मुकदमे को चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति जो आरोपी नहीं हैं, को अन्य आरोपी के साथ संयोजन करने तथा विचारण करने का निस्संदेह अधिकार क्षेत्र है, यदि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में साक्ष्य पर संतुष्ट है कि जिन व्यक्तियों को आरोपी के तौर पर संयोजित नहीं किया गया है अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत होने पर मुकदमे का सामना करना चाहिए। यह और भी स्पष्ट है कि व्यक्ति भले ही शुरू में प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था, मुकदमे का सामना करने के लिए जोड़ा जा सकता है। निचली अदालत ऐसे व्यक्तियों को केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी के रूप में जोड़ने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है, न कि आरोप पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप पत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री सबूत नहीं है। [पैरा 12] [74-जी-एच; 75-ए-बी]

जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य। एआइआर(1979) एससी 339 और दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य। , [1982] 1 एस. सी. सी. 2, पर विश्वास किया।

1.2 . धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा स्वतः या अभियुक्त सहित किसी के भी आवेदन पर किया जा सकता है, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के अलावा किसी

अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह शक्ति विवेकाधीन है और इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से, यह एक असाधारण शक्ति है जो न्यायालय को प्रदान की जाती है और इसका उपयोग बहुत कम और केवल तभी किया जाना चाहिए जब जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं की गई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ठोस कारण मौजूद हैं। धारा 319 में 'साक्ष्य' शब्द न्यायालय में दिए गए गवाहों के साक्ष्य पर विचार करता है। धारा 319 की उप-धारा 4 (1) (बी) के तहत, यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि यह माना जाएगा कि नया जोड़ा गया व्यक्ति एक आरोपी व्यक्ति था जब अदालत ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था। यह दर्शाता है कि उप-धारा 4 (1) (बी) के आधार पर, एक कानूनी कल्पना बनाई गई है कि यह माना जाएगा कि संज्ञान को नए जोड़े गए आरोपी की हद तक लिया गया है। [पैरा 13] [75-सी-ई]

लोक राम बनाम निहाल सिंह और अन्य। , [2006] 10 एस. सी. सी. 192, पर विश्वास किया।

2.1 . उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा है कि वास्तव में कोई आवेदन में देरी करने का तथ्य नहीं था । हालाँकि आरोप

पत्र 7.11.97 पर दाखिल किया गया था, 25.8.2003 पर आरोप विरचित किए गए थे। आदेशिका से पता चलता है कि देरी के लिए किसी भी तरह से शिकायतकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यदि जांच अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी की संतुष्टि को निर्धारक माना जाना है, तब धारा 319 Cr.P.C का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हालांकि यह हमेशा जांच अधिकारी की संतुष्टि नहीं हो सकती है, फिर भी इस मामले में उच्च न्यायालय को पीडब्लू-1 को स्वीकृति के योग्य नहीं होने का साबूत नहीं मिला। धारा 310 Cr.P.C के प्रयोजनों के लिए उसके साक्ष्य का मूल्य जो भी हो, उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। यह निष्कर्ष कि जाँच अधिकारी की संतुष्टि दी जानी चाहिए प्रधानता अस्थिर है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं ठहराया कि यह देर से लिया गया दृष्टिकोण था। [पैरा 8] [73-डी-ई]

2.2 . उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने और यह तय करने के लिए कि क्या पीडब्लू का स्वीकार्य है या नहीं, जांच अधिकारी से रिकॉर्ड मंगवाने के बाद का निष्कर्ष बहुत ही असामान्य प्रक्रिया है। इसलिए निचली अदालत को दंड संहिता की धारा 319 के संदर्भ में प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। पी. सी [पैरा 15 और 16] [75-एफ-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 2007 की 689

सीआरएल रिवीजन केस नंबर 1551/2004 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के अंतिम आदेश तथा निर्णय दिनांकित 07-10-2005 से।

संजय आर. हेगड़े, आदिश रेड्डी, विक्रांत यादव और अनिल के. मिश्रा अपीलार्थी के लिए।

जितेंद्र शर्मा, बी. के. पाल, पी. एन. झा और डी. भारती रेड्डी प्रत्यर्थी के लिए।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को दी गई है। अपीलार्थी और राज्य द्वारा दायर याचिका में विद्वान वी. एल. टी. एच. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गूटी, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), गूटी द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है।

3. अपीलार्थी द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार निम्नलिखित हैं -

4. 26.07.1997 को शाम लगभग 6 बजे, जब येद्दुला शिव प्रसाद रेड्डी(इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) एक मोटरबाइक पर आ रहा था, घातक हथियारों से लैस अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। पी. डब्ल्यू. 1 अपीलार्थी, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू की गई। Crl.आरसी संख्या में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए आवेदन पर। 1551 2004 में, अनंतपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाधीक्षक, गुंटकल द्वारा मामले की जांच कराई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, वर्तमान उत्तरदाताओं के नाम अभियुक्तों की श्रेणी से हटा दिए गए थे। उन्हें दाखिल आरोप पत्र दिनांक 07-11-1997 में शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद प्रकरण सेशन न्यायालय को दिनांक 10-11-1997 को कमिट कर दिया गया, जिसके एससी नंबर 378/1998 है। विचारण में विलंब था। इसके पश्चात पी0 ड0 1 दिनांक 07-07-2004 को परिक्षित हुआ। इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 319 के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई ताकि वर्तमान प्रतिवादियों को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। विद्वान सत्र न्यायाधीश याचिका को आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, कुछ निर्णायक निष्कर्ष देते हुए कि वर्तमान उत्तरदाताओं ने अपराध में भाग नहीं लिया है।

5. निचली अदालत ने धारा 319 के संदर्भ में किए गए आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बहाना की याचिका की पुलिस उपाधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत जांच की गई थी और उनकी गैर-संलिप्तता के बारे में अभियुक्त की याचिका में सार के बारे में उनकी संतुष्टि पर, उनके नामों को हटाने का निर्देश दिया गया था, खारिज कर दिया हालाँकि उनके नाम एफआइआर तथा गवाहों के कथनों में पाए गए फिर भी आरोपी के तौर पर हटा दिए गए। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाई और यह भी पाया कि आरोप पत्र 7.11.1997 पर दायर किया गया था। न तो लोक अभियोजक और न ही अपीलार्थी ने तुरंत कोई कदम उठाया। केवल 7.7.2004 पर एक आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि सबसे पहले अपीलार्थी और लोक अभियोजक को लगभग 7 वर्षों की इतनी लंबी अवधि तक चुप नहीं रहना चाहिए था। तथ्य यह है कि वे इतने लंबे समय तक चुप रहे, उच्च न्यायालय के अनुसार, यह दर्शाता है कि अन्यत्र रहने की दलील जो थी उस पहलू की जांच करने वाले विशेष जांच अधिकारी ने इसे सही पाया। उच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि इस तर्क में बल था कि राजनीतिक गुटों के कारण प्रतिवादियों को गलत तरीके से फंसाया गया था और सरकार के परिवर्तन के कारण, लोक अभियोजक याचिका दायर की थी। चूंकि पुलिस उपाधीक्षक ने अन्यत्र रहने की दलील को सही पाया था, इसलिए यह तथ्य

कि मुकदमे के दौरान गवाहों ने अन्यथा कहा था, वास्तव में कोई परिणाम नहीं था।

6. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश कायम नहीं हो सकते। कथित घटना 26.7.1997 पर हुई थी। आरोप पत्र 7.11.1997 पर दाखिल किया गया था और 25.8.2003 पर आरोप तय किए गए थे। आरोप तय करने में देरी के लिए किसी भी तरह से शिकायतकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पीडब्लू 1 की जाँच 7.7.2004 पर की गई थी और उसके साक्ष्य दर्ज होने के तुरंत बाद, संहिता की धारा 319 के संदर्भ में आवेदन दायर किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि आवेदन करने में देरी हुई थी। आरोप तय होने से पहले संहिता की धारा 319 के संदर्भ में किसी भी आवेदन के दायर होने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

7. जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसके बाद पूरी तरह से जांच करने पर, जांच अधिकारी ने अन्यत्र रहने की दलील को स्वीकार कर लिया था। उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज करना न्यायपूर्ण था।

8. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा है कि वास्तव में आवेदन करने में कोई देरी नहीं हुई थी। हालाँकि आरोप पत्र 7.11.1997 पर दाखिल किया गया था, लेकिन 25.8.2003 पर आरोप तय किए गए थे। आदेश पत्र से पता चलता है कि देरी के लिए किसी भी तरह से शिकायतकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में एक बुनियादी भ्रांति है। इसने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि क्या की गई जांच को पीडब्लू-1 के साक्ष्य के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए, फाइल को मंगवाया। यदि जाँच अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी की संतुष्टि को निर्धारक माना जाए, तो संहिता की धारा 319 का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हालांकि यह हमेशा जांच अधिकारी की संतुष्टि नहीं हो सकती है जो प्रबल है, फिर भी तत्काल मामले में उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य को स्वीकृति के योग्य नहीं पाया है। संहिता की धारा 319 के प्रयोजनों के लिए उसके साक्ष्य का मूल्य जो भी हो, उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। यह निष्कर्ष कि आई. ओ. की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं ठहराया कि यह देर से लिया गया दृष्टिकोण था।

9. धारा 319 संहिता के दायरे को जोगिंदर सिंह और अन्य में बनाम पंजाब राजय और अन्य। , ए. आई. आर. (1979) एस. सी. 339 में इस

न्यायालय के कई निर्णयों स्पष्ट किया गया है ::

6. धारा 319 (1) का एक सादा पठन) जो अध्याय XXIV में आता है, पूछताछ और परीक्षणों के संबंध में सामान्य प्रावधानों से निपटना, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह सत्र न्यायालय सहित सभी न्यायालयों पर लागू होता है और सत्र न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को जोड़ने की शक्ति होगी, न कि अभियुक्त इससे पहले, लेकिन जिसके खिलाफ मुकदमे के दौरान पेश होता है अपराध में उसकी संलिप्तता का संकेत देने के लिए पर्याप्त सबूत अभियुक्त और उसे अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने का निर्देश दें।

10. इसे पैराग्राफ 9 में आगे देखा गया थाः

> " 9. इस तर्क के संबंध में कि वाक्यांश 'कोई भी व्यक्ति, जो अभियुक्त नहीं है, जो धारा 319 में प्रयुक्त हुआ है, अभियुक्त जिसे पुलिस ने धारा के तहत रिहा कर दिया है, । इसके संचालन से बाहर है और आरोप पत्र के कॉलम संख्या 2 में दिखाया गया है, तर्क को केवल अस्वीकार कहा जाना चाहिए। उक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है जिस पर पहले से ही न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है और धारा 319 (1) इस तरह के प्रावधान को अधिनियमित करने का उद्देश्य यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि

उन व्यक्तियों को भी जिन्हें जांच के दौरान पुलिस ने छोड़ दिया है लेकिन जिनके खिलाफ सबूत दिखा रहे हैं अपराध में संलिप्तता आपराधिक न्यायालय के समक्ष आती है ।

11. दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और [1983] 1 जोगिंदर सिंह के मामले में फैसले का हवाला देने के बाद यह देखा गया थाः

> " 19. इन परिस्थितियों में, इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष किसी भी चरण साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जो न्यायालय को संतुष्ट करता है कि अन्य अभियुक्त या जिन्हें अभियुक्त के रूप में नहीं रखा गया है जिनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई है और अपराध भी किया है अदालत उनके खिलाफ संज्ञान ले सकती है और अन्य अभियुक्त के साथ मुकदमा चला सकती है। लेकिन, हम यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि यह वास्तव में गैर असाधारण शक्ति है, जो न्यायालय को प्रदान की जाती है और बहुत कम उपयोग की जानी चाहिए और केवल तभी जब अन्य व्यक्ति के विरूद्ध जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है लेने के लिए मजबूर करने वाले कारण मौजूद हों। इस स्तर पर इससे आगे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम पूरा मामला अदालत के विवेक पर छोड़ते हैं। ताकि वह कानून के अनुसार कार्य कर

> सके। यह स्पष्ट करें कि केवल तथ्य यह है कि कार्यवाही की गई है प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के खिलाफ अदालत को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा यदि यह पूरी तरह से संतुष्ट है कि उनके खिलाफ संज्ञान लेने का मामला अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर लिया गया है"

12. धारा 319 संहिता के साथ-साथ उपरोक्त दोनों निर्णयों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से, यह स्पष्ट हो जाता है कि निचली अदालत के पास निस्संदेह अधिकार क्षेत्र है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके सामने आरोपी नहीं है, अन्य अभियुक्त के साथ मुकदमे का विचारण में जोड सकता है, यदि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में संतुष्ट है साक्ष्य से कि जिन व्यक्तियों को इस रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है, को मुकदमे का विचारण करना चाहिए। यह आगे स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति भी हालांकि शुरू में एफ. आई. आर. में एक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, लेकिन आरोप पत्र में नहीं, मुकदमे का सामना करने के लिए भी जोड़ा जा सकता है। निचली अदालत केवल प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को आरोपी के रूप में जोड़ने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है। उसके समक्ष न कि आरोप-पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप-पत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री साक्ष्य नहीं है। बेशक, जैसा कि सोहन लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ए.

आई. आर. (1990) एस. सी. 2158 में बताए गए निर्णय से स्पष्ट है। एक अभियुक्त की स्थिति जिसे आरोपमुक्त कर दिया गया है, एक अलग स्थिति पर है।

13. धारा 319 संहिता की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा स्वतः या किसी के आवेदन पर जिसमें आरोपी भी शामिल हो, किया जा सकता है। यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। शक्ति विवेकाधीन है और इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से, यह एक असाधारण शक्ति है जो न्यायालय को प्रदान की जाती है और इसका उपयोग बहुत कम और केवल तभी किया जाना चाहिए जब किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद हों, जिसके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं की गई थी। धारा 319 में "साक्ष्य" शब्द अदालत में दिए गए गवाहों के साक्ष्य पर विचार करता है। उपरोक्त प्रावधान की उप-धारा (4) (1) (बी) के तहत, यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यह माना जाएगा कि नया जोड़ा गया व्यक्ति एक आरोपी व्यक्ति था जब - न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था। यह दर्शाता है कि उप-धारा (4)

(1) (बी) के आधार पर एक कानूनी कल्पना बनाई गई है कि संज्ञान को इस तरह लिया गया माना जाएगा। जहाँ तक नए जोड़े गए अभियुक्त का संबंध है।

14. उपरोक्त स्थिति को लोक राम बनाम निहाल सिंह और एन. आर. , [2006] 10 एससीसी 192। में उजागर किया गया था।

15 उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए तथा यह तय करने के लिए कि पी0ड0 1 का संस्करण उसे स्वीकार किया जाना था या नहीं, यह जांच अधिकारी से अभिलेखों को मंगवाने के बाद लिया गया निष्कर्ष बहुत ही असामान्य प्रक्रिया है।

16. नतीजतन, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से अक्षम्य है और खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय संहिता की धारा 319 के संदर्भ में प्रत्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कदम उठाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अपील को स्वीकार करके हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रोहित शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।